समुचित भोजन जरूरी

जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है. लेकिन, कुछ भी खाकर पेट भरने की मजबूरी या लापरवाही जान भी ले सकती है. लांसेट मेडिकल जर्नल में छपे शोध के मुताबिक दुनियाभर में 2017 में 1.10 करोड़ लोगों की मौत अस्वास्थ्यकर भोजन से हुई थी. यह संख्या तंबाकू सेवन से होनेवाली मौतों से भी अधिक है. इस अध्ययन में यह भी रेखांकित किया गया है कि कैंसर, हृदय रोगों, आघात, डायबिटीज आदि जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण खराब भोजन है. अनेक पूर्ववर्ती शोधों में भी खान-पान और विभिन्न बीमारियों के संबंध के बारे में आगाह किया गया है. जीवन शैली में बदलाव के कारण ठीक से भोजन करने पर लोगों का ध्यान कम हुआ है. आसानी से तैयार हो जानेवाले और डिब्बाबंद खाने का चलन तेजी से बढ़ा है. इस शोध में जिन मौतों का अध्ययन किया गया है, उनमें से आधे का कारण अन्न, फलों और सब्जियों का कम सेवन करना और भोजन में जरूरत से अधिक सोडियम का होना है. इस रिपोर्ट में सलाह दी गयी है कि चिकित्सक और पोषण विशेषज्ञ खाने-पीने में परहेज या कटौती पर जोर देने की जगह लोगों को फायदेमंद चीजें खाने को कहें. इस सलाह की वजह बताते हुए इस शोध के प्रमुख डॉ अश्कान आफशीन ने कहा है कि लोग जब कुछ चीजों का अधिक सेवन करने लगते हैं, तो कुछ दूसरी चीजों में कटौती भी करते हैं. अविकसित और विकासशील देशों में गरीबी और कम आमदनी बड़ी आबादी को समुचित भोजन से दूर कर देती है. इसका नतीजा कुपोषण, बीमारी और कमजोरी के रूप में सामने आता है. दूसरी तरफ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोग भोजन पर ज्यादा खर्च करने में समर्थ हैं, परंतु वे अधिक कैलोरी, वसा और स्टार्च ले रहे हैं. तली, नमकीन और मीठी चीजों का स्वाद लत में बदलता जा रहा है. वर्ष 2011-12 में नेशनल सैंपल सर्वे ने देश में भोजन की विषमता पर जारी रिपोर्ट में बताया था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा अंतर है. तब भारत में शहरी आबादी के सर्वाधिक धनी पांच फीसदी हिस्से का प्रति व्यक्ति हर महीने भोजन का खर्च 2,859 रुपये था, जो सबसे गरीब पांच फीसदी ग्रामीण आबादी के खर्च से करीब नौ गुना ज्यादा था. कम गुणवत्ता के भोजन के साथ मिलावट, रसायनों के बेतहाशा इस्तेमाल और खराब पानी जैसी मुश्किलों को जोड़कर देखें, हालात बेहद खराब नजर आते हैं. केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संबद्ध विभागों को नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण में भोजन से जुड़े वैज्ञानिक और आर्थिक अध्ययनों का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए. इन मसलों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी आवश्यक है तथा इस कार्य में मीडिया और नागरिक समाजों को अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए. चिकित्सकों और अस्पतालों के अन्य कर्मियों को नये शोधों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे लोगों को अच्छा खाने के लिए प्रेरित कर सकें. हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी तरह जीने और स्वस्थ जीवन में अंतर होता है.

केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संबद्ध विभागों को नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण में भोजन से जुड़े वैज्ञानिक और आर्थिक अध्ययनों का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए.

तेज आर्थिक वृद्धि की कोशिश

आरके पटनायक

पूर्व सेंट्रल बैंकर

editor@thebillionpress.org

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 अप्रैल 2019 को संपन्न चालू वित्तीय वर्ष के अपने पहले द्वैमासिक फैसले में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कमी कर दी. इसके दो माह पूर्व 7 फरवरी को भी इस समिति ने इस दर में इतनी ही कटौती की थी. यानी मौद्रिक नीति के संदर्भ में समिति का रुख तटस्थ बना रहा. यह सब बाजार की प्रत्याशाओं के अनुरूप ही था, हालांकि कुछ क्षेत्रों से और भी उदारता की मांग की जा रही थी.

इस समिति ने अपना यह फैसला दो के विरुद्ध चार मतों के बहुमत से किया. रेपो दर वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से अल्पकालिक ऋण लेकर अपने ग्राहकों को ऋण दिया करते हैं. रेपो दर में कमी के लाभ स्वरूप ग्राहकों को भी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है. मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो में इस कटौती का उद्देश्य 'सुस्त निजी निवेश में तेजी लाकर घरेलू वृद्धि उत्प्रेरणों को मजबूती देना' बताया गया. इसके अलावा, इस फैसले में ये कारक भी सहायक रहेः (क) अक्तूबर 2018 से ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में लगातार गिरावट, जो फरवरी 2019 में 2.6 प्रतिशत पर आ गयी; (ख) वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए महंगाई अनुमानों का 2.4 प्रतिशत पर, वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के लिए 2.9-3.0 प्रतिशत और दूसरी छमाही के लिए 3.5-3.8 प्रतिशत पर नरम बने रहना. गौरतलब है कि महंगाई की इन दरों का अर्थ उसके औसतन चार प्रतिशत से नीचे की निर्धारित दर के अनुशासन में कायम रहना है; (ग) महंगाई दरों के कम और नरम बने रहने के अनुमानों ने अर्थव्यवस्था के नकारात्मक आउटपुट अंतर के संदर्भ में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय करने दिये. नकारात्मक आउटपुट अंतर का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था का वास्तविक आउटपुट उसकी आउटपुट क्षमता से कम है; और (घ) रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण में पिछले सर्वे की तुलना में आगामी तीन महीने एवं एक वर्ष की अवधियों के पूर्वानुमानों में 40 आधार अंकों की कमी आ जाना.

इस तरह महंगाई दर में नरमी के आकलन और अर्थव्यवस्था को विकास के एक तेज रास्ते पर ले जाने का उद्देश्य रेपो दर में इस कमी का आधार बना. मुद्रास्फीति की उपर्युक्त प्रत्याशाओं के सामने तीन जोखिम तो अपनी जगह बनी हुई हैंः वर्ष 2019 में एल नीनो प्रभाव की संभावना, (ख) सब्जियों की कीमतें अचानक उलट जाने के खतरे, तथा (ग) निम्न ईंधन मुद्रास्फीति का अनिश्चित बने रहना.

रेपो दर में कमी को लेकर एक प्रासंगिक प्रश्न विवादास्पद रहा है, वह यह कि क्या इसके नतीजे में बैंक भी अपनी ब्याज दरों में कमी लायेंगे? जैसा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी के परिणामस्वरूप बैंकों ने अपनी ब्याज दरें मात्र 10 आधार अंक नीचे लायीं. इनके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में निम्न कारकों को लेकर अभी ये अनिश्चितताएं भी मौजूद हैंः (क) आगामी आम चुनावों और एक नयी सरकार के गठन को लेकर अस्पष्टताएं, (ख) एक नियमित बजट का पेश होना बाकी है, (ग) सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता से संबद्ध रिजर्व बैंक के पिछले निर्देश खारिज कर दिये जाने के बाद विनियमन संबंधी उसके अगले फैसले तथा कार्रवाइयां, (घ) कोर मुद्रास्फीति का उच्च स्तर, (च) वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी के मद्देनजर विकसित एवं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर उसका असर, (छ) निम्नतर वैश्विक वृद्धि एवं व्यापारिक अनिश्चितताओं की वजह से वित्तीय बाजारों में उठा-पटक, तथा (ज) केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तरों पर एक कमजोर राजकोषीय परिस्थिति.

> आर्थिक वृद्धि में एक सतत बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था में बचत के सतत बढ़ते जाने पर आधारित होना चाहिए. ऊंचा राजस्व घाटा बने रहने की राजकोषीय स्थिति अर्थव्यवस्था पर लगातार एक बोझ है.

मौद्रिक नीति के माध्यम से वृद्धि को प्रोत्साहित करने की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि उधार लेने के लिए सरकार की सकल जरूरतें बढ़ी होने की वजह से ब्याज दरों पर दबाव बनता है, जिससे ब्याज दर गिरावट के अल्पावधि ब्याज दरों से दीर्घावधि ब्याज दरों तक संचारित होने में बाधाएं आती हैं. सच तो यह है कि आर्थिक वृद्धि में एक सतत बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था में बचत के सतत बढ़ते जाने पर आधारित होना चाहिए. ऊंचा राजस्व घाटा बने रहने की राजकोषीय स्थिति अर्थव्यवस्था पर लगातार एक बोझ है. यह जब तक बना रहता है, वृद्धि जनित व्यय हेतु ऋण आधारित संसाधन की उपलब्धता समाप्त करता जाता है. इसलिए राजस्व घाटा खत्म करना बहुत जरूरी है, पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2018 ने राजस्व घाटा खत्म करने पर गौर नहीं किया.

ब्याज दर में कमी पर मौद्रिक नीति समिति का फैसला सर्वसम्मत नहीं रहा. फरवरी एवं अभी के दोनों फैसलों में दो सदस्यों ने यथास्थिति के पक्ष में मत दिये, पर चूंकि चार सदस्यों के मत उसमें परिवर्तन हेतु थे, अतः वैसा ही हुआ. क्या यह परिपक्वता का सूचक है? क्या बहुमत के निर्णय को सही मानना हमेशा ही उचित होता है? इन प्रश्नों पर बहस जरूरी है. लगता है हालिया अरसे में मुद्रास्फीति में आयी कमी वास्तविक की बजाय तकनीकी ही रही है, जिसके विपरीत दिशा में जाने की संभावनाएं भी मौजूद रहेंगी. इसके अतिरिक्त, आर्थिक वृद्धि में ब्याज दर की कमी द्वारा बढ़ोतरी लाना सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिक कम. ऋण वितरण के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक कमजोरियां हैं, जिनका डूबत ऋणों (एनपीए) का ऊंचा स्तर भी साथ दे रहा है. वित्तीय बाजार अभी इतने परिपक्व नहीं हो सके हैं कि मौद्रिक नीति को पूरी तरह प्रतिबिंबित कर सकें. ऐसे में, यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि ब्याज दरों में लायी गयीं दो लगातार गिरावटें अनुपयोगी होंगी.

यह मानते हुए कि रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति रुख तटस्थ रहेगा, मॉनसून सामान्य होगा और साथ ही खाद्य तथा ईंधन मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति और औसत खुदरा मुद्रास्फीति का स्तर लगातार चार प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर ही रहेगा, अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने की कवायद विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन (यानी राजस्व घाटे की समाप्ति) मजबूत करने और श्रम सुधारों के अलावा बैंकिंग प्रणाली द्वारा ऋण वितरण की कड़ी मॉनिटरिंग पर निर्भर होगी. ब्याज दरों में कमी लाने की मार्फत मौद्रिक नीति से काम लेने पर अत्यधिक निर्भरता संभवतः ज्यादा कारगर सिद्ध न हो सके.

(अनुवादः विजय नंदन)

मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई

पैट्रिशिया हॉफमैन

यूएस कॉन्सुल जनरल, कोलकाता

delhi@prabhatkhabar.in

> हम इस बात को महसूस करते हैं कि भारत की सरकार के साथ हमारी सहभागिता अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, पर मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकारों की ही जवाबदेही नहीं है.

मानव तस्करी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है. यह कानून के शासन को कमजोर करता है, लाखों लोगों को उनकी गरिमा और आजादी से वंचित करता है, संलग्न अपराधियों को समृद्ध करता है, और दुनियाभर में जनता की सलामती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है. मानव तस्करी में संलग्न अपराधियों द्वारा पीड़ितों पर ढाये जानेवाले बेइंतहा जुल्म से कोई भी धर्म, देश या समुदाय अछूता नहीं है.

मानव तस्करी में संलग्न अपराधियों को रोकने, पीड़ितों को संरक्षण देने और इन अपराधियों के फलने-फूलने में मददगार व्यवस्थाओं को नष्ट करने हेतु नीतियों और कानूनों को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका दुनियाभर में सरकारों के साथ निरंतर सहयोग कर रहा है. हम मानव तस्करी के हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए सहभागी गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं. मानव तस्करी के खिलाफ किसी भी देश की प्रतिक्रिया मुकम्मल नहीं है और हम सभी इस संबंध में लगातार सीख रहे हैं, नयी तकनीकों को अपना रहे हैं, और अपने तौर-तरीकों को बेहतर बना रहे हैं.

अगर भारत की बात करें, तो अमेरिका निरंतर ही भारतीय सरकार और यहां के गैरसरकारी संस्थानों को '3पी' प्रतिमान- मानव तस्करी मामलों में अभियोजन (प्रॉसेक्यूशन), पीड़ितों की रक्षा (प्रोटेक्शन) और मानव तस्करी की रोकथाम (प्रिवेंशन)- के तहत मजबूत बनाने में मदद कर रहा है. इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कोलकाता स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट ने बीते 13-16 मार्च तक मानव तस्करी-रोधी युवा चैंपियनों के आठवें सम्मेलन (एट्थ एंटी-ट्रैफिंग इन पर्सस यूथ चैंपियंस कॉन्क्लेव) की मेजबानी की. सरकार और सिविल सोसाइटी के नेताओं और युवा सहभागियों को एकजुट कर यह सम्मेलन मानव तस्करी के विरुद्ध काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की अगली पीढ़ी का सशक्तिकरण करता है तथा हमें एकजुट होने और समाधानों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

इस साल के सम्मेलन में विदेश विभाग की डिजिटल कथा वाचन पहल 'मानव तस्करी का उन्मूलन : एक बार में एक कहानी' को भी शामिल किया गया था, जिसके तहत मानव तस्करी की पीड़ा झेल चुके आठ व्यक्तियों को मानव तस्करी के खिलाफ उम्मीद और विजय की उनकी यात्राओं को साझा करने के वास्ते लघु फिल्में बनाने के लिए एक साथ लाया गया. इस नयी पहल ने सम्मेलन के सहभागियों को मानव तस्करी के पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदायों पर पड़नेवाले प्रभाव के बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने का काम किया. पीड़ित व्यक्तियों के अनुभव मानव तस्करी के खिलाफ हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

यहीं पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार सफलतापूर्वक स्वयंसिद्ध अभियान चला रही है, जिसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक परीक्षण परियोजना के तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले में शुरू किया था. मानव तस्करी-रोधी लड़ाई में छात्रों और सामुदायिक समूहों को शामिल करने पर केंद्रित इस अभियान ने युवा महिला नेताओं की फौज खड़ी कर दी है. वास्तव में, अब इस मॉडल को राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जानेवाला है. गत वर्ष, अपने मानव तस्करी विरोधी सम्मेलन में स्वयंसिद्ध अभियान की सफलता को प्रस्तुत करना हमारे लिए सम्मान की बात थी, और हमारी योजना भारत के अन्य राज्यों के साथ इस मॉडल को साझा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य प्रमुख सहभागियों के साथ काम करना जारी रखने की है.

अमेरिका के लिए पीड़ितों की आवाज को सुनने का एक और जरिया यूएस एडवाइजरी कौंसिल ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग है. इस संस्था में राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सिर्फ मानव तस्करी का शिकार रहे व्यक्तियों को शामिल किया गया है. एडवाइजरी कौंसिल राष्ट्रीय मानव तस्करी-रोधी नीतियों पर अमेरिका सरकार को सलाह और अनुशंसाएं करने के लिए पीड़ितों को एक औपचारिक मंच प्रदान करती है. यह सरकार के प्रयासों को आकार देने में पीड़ितों का योगदान सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम प्रगति है.

सम्मेलन में यौन शोषण के लिए मानव तस्करी में इंटरनेट की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा हुई और इसके खिलाफ निजी क्षेत्र को अहम साझेदार बनाने के महत्व पर जोर दिया गया. इस अवसर पर अमेरिका के टेक्सस क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की डॉ वनेसा बुशे और उनके छात्रों ने कैंपस सक्रियता, सामुदायिक सक्रियता और पेशेवर सक्रियता पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया.

भारत में ऐसे सम्मेलनों के जरिये हो रहे जमीनी प्रयासों का अमेरिका समर्थन करता है. हम इस बात को महसूस करते हैं कि भारत की सरकार के साथ हमारी सहभागिता अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, पर मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकारों की ही जवाबदेही नहीं है. सिविल सोसाइटी की पहलकदमियां, जिन पर सालाना सम्मेलन में विचार किया गया, सफलता पाने के लिए आवश्यक और अहम हैं. साथ मिलकर काम करने पर ही हम उस दौर में पहुंचने की कल्पना कर सकते हैं, जब मानव तस्करी में संलग्न अपराधी बेखौफ होकर काम नहीं कर पायेंगे.

बोधि वृक्ष

ज्ञान प्रक्रिया

ज्ञान प्रक्रिया को सामान्य भाषा में कहा जाता है कर्मभाव का कर्तृभाव में रूपांतरण. अब जो कुछ भीतर या बाहर है, उसको मन विषय में परिणत करके उसका किसी प्रकार आत्मस्थीकरण कर सकने को ही कहा जायेगा पराज्ञान. और जहां पूरा आत्मस्थीकरण नहीं हुआ, वह अपराज्ञान या आपेक्षिक ज्ञान है. इसलिए परम लक्ष्य में पहुंचने के लिए केवल सत्य ही नहीं, इस आत्मस्थीकरण का भी प्रयोजन है. अब द्वितीय उपाय अर्थात् कर्म के प्रसंग को लें. क्योंकि कर्म जो करेगा, वह तो पाशयुक्त जीव है. कर्म के द्वारा जब साधक की मुक्ति होगी, तब कर्म को भी अवश्य ही प्रभाव मुक्त होना होगा. अतः मन को बंधन के बाहर ले जाने के लिए उसे किसी ईश्वरीय सत्ता के साथ संपर्कित होना होगा. कर्म की परिभाषा है- वस्तु का स्थान परिवर्तन. जहां स्थान का प्रश्न आता है, वहां काल और पात्र का भी प्रश्न आयेगा. इसलिए केवल कर्म के माध्यम से मनुष्य कैसे परमपद को पा सकता है? मान लो, मेरी दाईं ओर एक पुस्तक है; पुस्तक को हटाकर बाईं ओर रखा. पुस्तक का स्थानांतरण हुआ; एक कर्म निष्पन्न हुआ. यह जो क्रिया है, काल और स्थान के परिवर्तन के साथ-साथ वह भी बदल जाती है. अतः इस प्रकार के कर्म-संपादन के द्वारा मनुष्य चरम आध्यात्मिक अवस्था या जीवन के अंतिम लक्ष्य में नहीं पहुंच सकता है. शास्त्र में कहा गया है- कर्म ही ब्रह्म है और इसलिए अधिक से अधिकतर कर्म का अनुष्ठान करो. अब कर्म का अर्थ है वस्तु का स्थान परिवर्तन. इसलिए कर्म के द्वारा मनुष्य कैसे मुक्ति पा सकता है? अब तृतीय उपाय है भक्ति. भक्ति योग शुरू होता है मानस स्तर से, किंतु उसका लक्ष्य रहता है मानस परिधि के बाहर. इसी तरह किसी मनोजागतिक विषय में भी चित्तवृत्ति निबद्ध होने से वह भी गुणबंधन के दायरे में आ जाता है, यहां तक कि आध्यात्मिक मामले में भी मनुष्य यदि जीवात्मा को उसका ध्येय बना लेता है, तब वह भी पूरी तरह से गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है. अतः जब किसी का लक्ष्य संपूर्ण गुणातीत होंगे, तभी साधना में परम सिद्धि होगी.

श्रीश्री आनंदमूर्ति

आपके पत्र

कश्मीर का हल कश्मीरियों का दिल जीतकर ही होगा

किसी के घुटने में घाव हो जाए और ठीक होने का नाम ही न ले, तो क्या पैर को ही काटकर फेंक देना चाहिए. क्या यही इसका सही इलाज है? मुझे लगता है- नहीं. क्योंकि भारत के गृह मंत्रालय ने जो श्रीनगर-जम्मू हाईवे को सप्ताह में दो दिन, रविवार और बुधवार को 31 मई तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया है, वह किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है. 274 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में आम नागरिक, शेष भारत से ट्रकों के द्वारा आवश्यक सामान आता-जाता है. नागरिकों और ट्रांसपोर्टरों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? बुधवार और रविवार को जो जहां तक पंहुचा है, उसके बाद उसे 24 घंटे के लिया जहां का तहां खड़ा हो जाना पड़ेगा? कश्मीर समस्या का हल बिना कश्मीरियों के दिल जीते नहीं हो सकता.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

कांग्रेस को नहीं देनी चाहिए दूसरी पार्टियों के फैसले में दखल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में महाराष्ट्र और उसके बाद हरिद्वार जो बयान दिया है, वह बेहद निंदनीय है. अब यह बिलकुल समझ से बाहर हो चुका है कि कांग्रेस वार-प्रतिवार और बयानबाजी में और किस हद तक गिरेगी. सबसे पहले तो यह बीजेपी का आंतरिक मामला है और कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पार्टी किसे टिकट दे या किसे न दे. कांग्रेस को अपनी पार्टी और चुनाव में अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए और अगर प्रतिक्रिया देनी ही है, तो उसका भी एक तरीका होता है. कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि ऐसी बयानबाजी कहीं चुनाव में उनके वोटों के नुकसान का कारण न बन जाए.

शुभम गुप्ता, धनबाद

वायनाड से चुनाव लड़ कर क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल

अमेठी में चुनौती कठिन होती देख राहुल गांधी ने अपने लिए एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश में वायनाड का चयन किया है. लेकिन, उन्हें यह आभास होना चाहिए कि यहां उन्हें कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के भरोसे रहना होगा. आखिर ऐसे दल के समर्थन से चुनाव लड़कर वह कांग्रेस के सेक्युलर होने के दावे को मजबूती कैसे दे सकते हैं? निःसंदेह यह पहली बार नहीं, जब किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने दक्षिण भारत से चुनाव लड़ा हो. इसके पहले इंदिरा गांधी चिकमंगलूर और सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ चुकी हैं. राहुल गांधी इनमें से किसी सीट का चयन कर सकते थे. कर्नाटक की सत्ता में तो कांग्रेस साझीदार भी है. वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले का मूल कारण जानना एक पहेली ही है. कहना कठिन है कि वायनाड के जरिये कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को एक पहेली का जो रूप दिया, उससे उसे क्या हासिल होगा?

डॉ हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर

कुछ अलग

सुराही-मटके के दिन!

क्षमा शर्मा

वरिष्ठ पत्रकार

kshamasharma1@gmail.com

गरमी आते ही फ्रिज, कूलर, एसी, ठंडे पेय की मांग बढ़ जाती है. खीरा, तरबूज, ककड़ी की बहार आ जाती है. सड़कों पर कहीं-कहीं घड़े दिखने लगते हैं. पहले रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर घड़े-सुराहियां दिखती थीं. मगर अब ऐसा कहीं-कहीं ही देखने को मिलता है. फूल-पत्तियों की डिजाइन से सजे मिट्टी के ये बरतन बहुत सुंदर दिखते थे. रेलवे स्टेशनों या बस अड्डों पर बने प्याऊ में बड़े-बड़े मटकों में पानी रखा रहता था.

रेल के सफर में लोग अपने साथ एक सुराही जरूर ले जाते थे. फिर जहां उतरते थे, सुराही को डिब्बे में ही छोड़ जाते थे. सुराही का यह पानी न केवल अपनी, बल्कि अपने साथ के भी कई यात्रियों की प्यास बुझाया करता था. सुराही का मतलब होता था, रास्ते भर ठंडा पानी मिलना. अब बोतल बंद पानी की हर जगह उपलब्धता ने रास्ते के लिए सुराही में पानी भर कर ले जाने के रिवाज को खत्म कर दिया है.

श्रवण कुमार की कथा अगर आपको याद हो, तो वह अपने माता-पिता के लिए नदी से मटके में पानी ही तो भरने गया था. घड़े में पानी भरने से जो आवाज हुई, उसे किसी पशु की आवाज समझकर दशरथ ने तीर चला दिया और श्रवण कुमार मारा गया था. पुराने जमाने में तो पैदल यात्री भी पानी की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए घड़ा साथ में रखते थे.

लेकिन जब से फ्रिज घर-घर में आया, घड़े की उपयोगिता कम होती गयी है. फ्रिज के पानी में मिट्टी की वह खुशबू कहां, जो घड़े या मटके और सुराही के पानी में होती थी. हालांकि, अब भी कुछ लोग घड़े खरीदते हैं. बाजारों में तरह-तरह के पेंट से पुते घड़े दिखायी देते हैं. बहुतों में नल भी लगे होते हैं. लेकिन सुराहियां शायद ही कहीं दिखायी देती हैं.

दिल्ली में मथुरा रोड पर पुराने किले के पास 784 साल पुराना सूफी संत हजरत शेख अबू बकर की दरगाह है. अकसर गुजरते हुए यहां के पेड़ों पर मटके लटके दिखायी देते हैं. इसे मटका पीर के नाम से भी जाना जाता है.

इन दिनों मिट्टी के घड़े तो कहीं-कहीं दिखायी दे भी जायें, लेकिन सुराहियां तो कम ही दिखायी देती हैं. सुराहीदार गरदन की उपमा महिलाओं के लिए दी जाती थी, लेकिन अब सुराही ही नहीं बची, तो कोई नयी उपमा ढूंढी जानी चाहिए. सफर में तो अब इनका की काम नहीं रहा. बोतल बंद पानी के व्यवसाय ने इन्हें खदेड़ दिया. युवाओं को तो यह मालूम भी नहीं होगा कि कभी रास्ते में पानी की जरूरत सुराहियां पूरी करती थीं.

पहले के दौर में गरमी आते ही घर में सबसे पहले घड़ा खरीदा जाता था. जब उसे धोकर उसमें पानी भरा जाता था, तो मिट्टी की खुशबू सारे घर में फैल जाती थी.

नये के फेर में अकसर हम बहुत-सी कलाओं को भुला देते हैं. कुम्हार की कला भी वैसी ही है. चाक पर चलते कुम्हार के हाथ और किसी जादू की तरह कभी मटका बनना, कभी सुराही, कभी कटोरा, कभी मिट्टी का तवा, कभी कुल्हड़. जिसने भी यह नजारा देखा है, वह उसे कभी भूल नहीं सकता.

देश दुनिया से

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित बच्चे

एक आकलन है कि दुनियाभर में करीब तीन अरब से ज्यादा लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित हैं. और सबसे खास बात यह है कि यह स्थिति विकासशील देशों में ज्यादा है. इन देशों में पाकिस्तान सबसे खराब स्थिति वाले देशों में है, जहां पांच वर्ष की उम्र के आसपास के बच्चों के पोषण की स्थिति बेहद कमजोर है. पाकिस्तान में पांच साल से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे छोटे कद के हैं और इसमें भी तीन में से एक कमवजनी

DAWN

का शिकार है. बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हैं और उनकी बचपन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिस्थिति बच्चों में रोगों की संख्या को बढ़ानेवाली है और कम उम्र में ही मृत्यु दर को बढ़ावा देनेवाली है. यही नहीं, मिट्टी में कम सूक्ष्म पोषक तत्व तो हैं ही, सामान्य लोगों के बीच पोषण को लेकर बेहद कम जानकारियां भी हैं. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान में भोजन से संबंधित रणनीतियां पूरी तरह से विफल रही हैं. इसलिए अब जरूरी है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए मीडिया के माध्यम से पोषण-जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाये. यह अच्छी बात नहीं है कि पौष्टिक भोजन से बच्चे महरूम रहें.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है